

राहुल गाँधी की, फ्रैश, साफ छवि वाले जिलाध्यक्ष बनाने की योजना राजस्थान में क्यों फेल हो रही है

यह कार्यक्रम देश भर में जोर-शोर से आगे बढ़ रहा है, पर, राजस्थान में आकर फिसड़ी हो गया है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान शुरू कर साफ-सुथरी और प्रभावी राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अभियान के तहत, जिलाध्यक्षों को अधिक अधिकार और मजबूती देने के लिए कुछ मानक और नियम तय किए गए हैं, ताकि संगठन के संचालन में ऊर्जा और प्रभावशीलता बनी रहे। यह प्रक्रिया पूरे देश के कई राज्यों में चल रही है।

इस कार्य के लिए पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) को नियुक्त किया गया है, जिन्हें राज्य नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और अन्य स्वाधीन हितों को दरकिनार करते हुए, जिलाध्यक्षों के नामों की पैनल सूची तैयार करनी थी।

लेकिन राजस्थान में इन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। केन्द्र से मिले स्पष्ट निर्देशों की

■ राजस्थान में यह दो व्यक्तियों के कारण असफल होता नज़र आ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा।

■ स्पष्ट निर्देश थे कि दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो खोजबीन व छानबीन के बाद, नए जिलाध्यक्षों के नाम प्रस्तावित करेंगे।

■ यह भी स्पष्ट निर्देश थे कि प्रदेशाध्यक्ष व राज प्रभारी की इन नियुक्तियों में कोई भूमिका नहीं होगी।

■ पर, प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी ने बारह नामों की सूची भेजी है। इस सूची में वे नाम शामिल हैं, जो काफी हद तक विवादित हैं, जैसे प्रमोद सिसोदिया चित्तौड़गढ़, शबनम गोदारा हनुमानगढ़ तथा पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुर। इस तरह के कई नाम हैं, जो पुराने नेताओं व खेमेबाजी में भी सक्रिय रहे हैं।

अनदेखी करते हुए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी प्रभारी रंधावा ने 12 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेज दी हैं, जबकि, इसका अधिकार नहीं था तथा ऐसा न करने के निर्देश उन्हें पहले ही दे दिए गए थे, क्योंकि इस काम के लिए अलग से

पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम सुझाए गए हैं, उनमें कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि स्वच्छ छवि और प्रभावी जिलाध्यक्षों की मूल भावना के खिलाफ हैं। रंधावा, जिन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाए रखा गया है, किसी वेणुगोपाल के करीबी माने

जाते हैं, और वेणुगोपाल पार्टी में वास्तविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

रंधावा, डोटासरा, अशोक गहलोत और सी.पी. जोशी के गुट से जुड़े हुए हैं। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस आई भर्ती : अशोक गहलोत के पूर्व पी एस ओ को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव सहित पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अदालत ने पीएसओ के बेटे

■ हाई कोर्ट ने पीएसओ के पुत्र सहित नौ आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

भरत यादव सहित नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश 14 आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर हल करने वाले प्रवीण कुमार, सत्येन्द्र यादव, टेनी एसआई समेता कुमारी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 देशों के डिप्लोमैट्स की टीम चुनाव देखने बिहार गई

“नो भाजपा” (भाजपा को जानो) मुहिम के तहत दो दिन के प्रवास में इन डिप्लोमैट्स ने भाजपा के चुनाव प्रचार को करीब से देखा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा शुरू की गई “नो बीजेपी” (भाजपा को जानो) पहल के तहत जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के भारत में स्थित दूतावासों के राजनयिक प्रतिनिधियों का एक दल 2-3 नवम्बर 2025 को बिहार का दौरा करने के लिए गया, ताकि वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस प्रतिनिधिमंडल ने अररिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक रैली देखी, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार के

■ बिहार यात्रा में इन राजनयिकों ने प्र.मंत्री मोदी की आरा में हुई विशाल जनसभा देखी, कई-कई नेताओं से मुलाकात की तथा घर-घर चुनाव अभियान में गहरी रूचि ली।

■ “नो भाजपा” मुहिम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने शुरू की है।

■ डिप्लोमैट्स की टीम में जापान, यूनाईटेड किंगडम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान व भूटान के राजनयिक शामिल थे।

दौरान बहुत सारे लोगों की भागीदारी को देखा। अपने दौर के दौरान, राजनयिकों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं रविशंकर प्रसाद, धर्मेन्द्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात की और बुनियादी स्तर पर घर-घर जाकर हो रहे चुनाव प्रचार की

गतिविधियों को देखा। इसके बाद वे भाजपा के राज्य मुख्यालय पटना गए और पार्टी के संगठन, संचार रणनीति और चुनाव प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की।

पैसेंजर ट्रेन व मालगाड़ी की टक्कर में 7 की मौत

बिलासपुर, 04 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गयी, जिसमें सात यात्रियों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये।

दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन के पास शाम को करीब चार बजे हुयी जिसमें

■ बिलासपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई।

मेमू ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और जिला प्रशासन की टीमों मौके पर पहुंच गयीं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये’

जयपुर, 4 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केन्द्र व राज्य सरकार से 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए यह बताने के लिए कहा है कि अभी तक सड़क सुरक्षा नीति, ब्लैक स्पॉट सुधार योजना और वाहन जांच अभियान के तहत क्या कदम उठाए गए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संघू की

■ राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने 6 नवंबर तक जवाब मांगा।

खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है।

याचिका में कहा गया कि हाल में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेशभर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और इनमें लोगों की मौतें हुई हैं। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़क सुरक्षा के प्रति सरकारी लापरवाही, खस्ताहाल रोड, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की कमी और ट्रैफिक प्रबंधन की विफलता है। प्रदेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (यू) के कद्दावर नेता लल्लन सिंह पर चुनाव आयोग ने केस किया

लल्लन सिंह एक वायरल वीडियो में धमकाने वाला बयान देते हुए दिखे कि मतदान के दिन कुछ नेताओं को घर से नहीं निकलने देना है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 4 नवम्बर। बिहार में पहले चरण के हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 48 घंटे पहले, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू में नंबर 2 और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ एक पुलिस मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उनके चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने को लेकर दर्ज हुआ है।

लल्लन सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें वह एक वीडियो में यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि “कुछ नेताओं को मतदान के दिन उनके घर से बाहर जाने नहीं दिया जाना चाहिए।” यह एफआईआर चुनाव आयोग के आदेशों पर आर भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता

■ लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह खुद एक बाहुबली हैं तथा नीतीश के करीबी हैं। जद (यू) में उन्हें नीतीश के बाद नंबर दो माना जाता है।

■ मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा में दिए गए लल्लन सिंह के भाषण का वीडियो जारी किया।

■ मोकामा लल्लन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आता है, जहाँ से जद (यू) ने बाहुबली अनंत सिंह को टिकट दिया है। लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, जो खुद बाहुबली हैं, अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।

■ लल्लन सिंह ने दुलार सिंह यादव (एक अन्य पूर्व बाहुबली) की हत्या में अनंत सिंह का बचाव किया व कहा कि अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है।

दल ने पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लल्लन सिंह के भाषण का मुद्दा उठाया था, जो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब स्थानीय बाहुबली और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को हत्या

के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वायरल वीडियो में लल्लन सिंह यह कहते सुनाई दे रहे हैं, “कुछ नेताओं को चुनाव के दिन उनके घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर वे बहुत

ज़्यादा मांग करें, तो उन्हें अपने साथ ले जाओ और मतदान करने के बाद उन्हें घर वापस लेकर जाओ और बिस्तर पर सुला दो। उन्हें घर में बंद कर देना है। अब जिम्मेदारी संभालो। चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है।”

वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि लल्लन सिंह चुनाव आयोग पर बुलडोजर चला रहे हैं। “(वह कह रहे हैं) उन्हें बंद कर दो, अगर वे मिन्नत करें तो उन्हें मतदान करने ले जाओ। आरजेडी ने सवाल उठाया, मरा हुआ आयोग कहाँ है?”

मोकामा, जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लल्लन सिंह के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में आता है। इससे पहले, एक साक्षात्कार में उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को एक साजिश बताया था और कहा था कि आगामी चुनावों में बाहुबली अनंत सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारह राज्यों में एसआईआर का काम शुरू

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। चुनाव आयोग ने कहा कि 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू हो गया है।

चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार को बताया गया कि बिहार में

■ चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की।

एसआईआर के सफल समापन के बाद, इस अभ्यास के दूसरे चरण में नौ राज्यों (छत्तीसगढ़ , गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। इसमें तीन केन्द्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी) के 3.21 जिले और 1,843 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

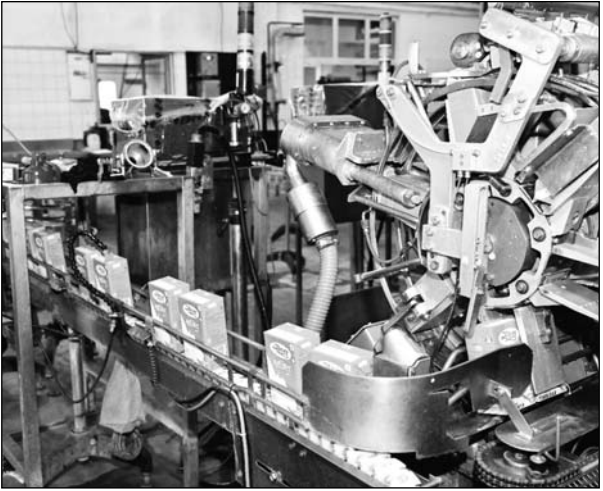
राजस्थान में डेयरी विकास के लिये 1००0 करोड़ रुपए का ‘‘कोरपस फण्ड’’ बनाने की मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा

—कार्यालय संवाददाता—

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए राज्यभर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिये 1000 करोड़ रुपये के “कोरपस फण्ड” बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के लिये जारी की गई है। डेयरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले दो दशकों में पहली बार यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। साथ ही डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में



इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। स्वीकृत राशि से राज्यभर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया

जावेगा। उन्होंने बताया कि अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लान्ट्स की स्थापना की जावेगी। इसके साथ ही सीकर-झुन्झुनू, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लान्ट्स का विस्तार एवं

- **राज्य सरकार के इस फैसले से आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता भी बढ़कर 75 लाख लीटर प्रतिदिन होगी**
- **इसके साथ ही पशु आहार उत्पादन क्षमता भी 2550 मैट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी**

सुदृढीकरण किया जायेगा। कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में भी नये अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जावेगी और जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण किया जावेगा। पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 60 मैट्रिक टन क्षमता के नये डेयरी प्लान्ट्स भी स्थापित किये जाएंगे। श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

इस बजट के कारण आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकेगी।

वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 2500 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। इसी प्रकार आरसीडीएफ के पाउडर प्लान्ट्स की वर्तमान क्षमता 165 मैट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 225 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि “कोरपस फण्ड” की 10 प्रतिशत राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा।

इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कोरपस फण्ड की 10 प्रतिशत राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जावेगी। कोरपस फण्ड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एचआईडीएफ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार और 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जावेगी।

‘गिवअप’ अभियान से जुड़कर 4 2 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं नाम हटवाया

इस कारण राज्य सरकार 69.50 लाख नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ सकी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 42 लाख अन्नज लोगों ने स्वयं “गिव अप” अभियान से जुड़कर खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। इससे अब पात्र और वंचित लोगों को फायदा मिलेगा।

प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। परंतु यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2024 को आरंभ हुए “गिव अप”

अभियान में प्रदेशभर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। करीब 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हो गए, जिससे नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69.50 लाख नए

- **खाद्य सुरक्षा योजना में कलैक्टर्स जोड़ सकेंगे लाभार्थी, लोग स्वयं हटा सकेंगे अपना नाम सूची से**

पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित

करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सक्षम लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये की दर से प्रतिवर्ग 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा और

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान सरकार की यह पहल ‘आपणे अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का आज से होगा सघन निरीक्षण

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ किया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींसर के निर्देशों पर प्रदेशभर में 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। सघन निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चिकित्सा संस्थान में इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स पूरे हों, जिन संस्थानों में यह स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं होंगे, वहां मिशन मोड में इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 5 से 7 नवम्बर तक सभी संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित हो कि एम्बुलेंस संचालन योग्य हों, उनमें सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हों और क्रियाशील स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह से अगस्त माह तक एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में कमियां पाई जाने पर 2 करोड़ रूपए से ज्यादा की फैनल्टी लगाई गई है।

प्रमुख शासन सचिव ने विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिले हर हाल में टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को 17 सीसीए के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं का भी सघन निरीक्षण किया जाए, जहां भी एम्बुलेंस संचालन में कमियां पाई जा रही हैं, वहां नियमानुसार फैनल्टी लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित हो कि एम्बुलेंस संचालन योग्य हों, उनमें सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हों और क्रियाशील स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह से अगस्त माह तक एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में कमियां पाई जाने पर 2 करोड़ रूपए से ज्यादा की फैनल्टी लगाई गई है।

देशभर से बैंक कर्मचारी नेता जयपुर में जुटेंगे

जयपुर । करीब 25 साल बाद ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए)केन्द्रीय समिति की राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन करेगी। महासचिव महेश मिश्रा ने बताया कि इससे पहले सन् 2000 में यह बैठक जयपुर में हुई थी। यह दो दिवसीय (5-6 नवम्बर) बैठक आज से एमआई रोड स्थित होटल गोल्डन टचयूलिएप में शुरू होगी। इसे एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सी एच वेंकटचलम संबोधित करेंगे। सम्मेलन में एआईबीईए के अध्यक्ष राजन नागर और सचिव बीएस रामबाबू के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 1०5 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक से पूर्व मंगलवार को तारक भवन में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के महासचिव महेश मिश्रा के नेतृत्व में सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें आरपीबीईयू के चेयरमैन आरजी शर्मा और उप महासचिव सूरज भान सिंह अमेरा सचिव महेश शर्मा भी मौजूद रहे।

शिक्षा संकुल में कूडेदान की जगह का कार्याकल्प कर बनाया सभागार

जयपुर । शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया। इसका नाम “माधव सभागार” रखा गया है। सभागार की कुल क्षमता 40 लोगों के बैठने की है। इसके निर्माण पर 35 लाख रुपये खर्च हुए हैं। जिस जगह सभागार का निर्माण किया गया है, वहां पूर्व में कूड़ादान था, जिसे अभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागार के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने भूतल पर नवनिर्मित एलीवेटर (लिफ्ट) का भी लोकार्पण किया। दिलावर ने बधाई देते हुए कहा कि, ये सभागार बहुत सुन्दर बना है, जो सभी प्रकार की बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोगी साबित होगा। भवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए नवीन एलीवेटर (लिफ्ट) प्रारम्भ होने से बहुत लाभ होगा। लोग आसानी से भवन के सभी कक्षों में पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर सभागार निर्माण में



शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया।

उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुमित तिवारी, अधिशाषी अभियंता, समग्र शिक्षा, महाराजा सक्सेना, सहायक अभियंता, समग्र शिक्षा तथा ओपन स्कूल के सहायक निदेशक गिरिराज गुप्ता, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर आशिता शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शासन सचिव शिक्षा

कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम , राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

परिणामस्वरूप छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं और नियमित कक्षाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण अनुसंधान कार्य भी बाधित हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक रैंकिंग तथा प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंच रही है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया

सोधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर

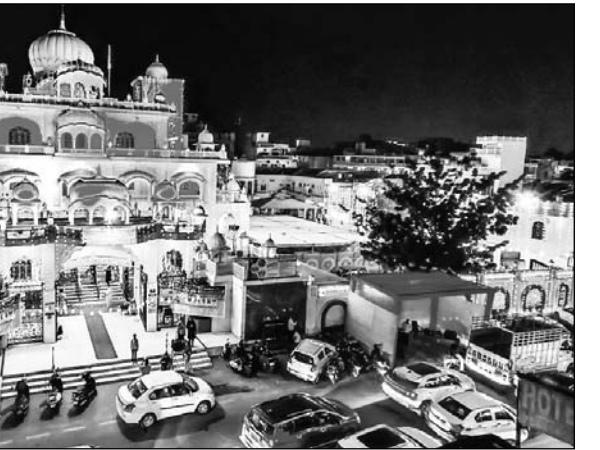
विषय पर तत्काल आवश्यक लेजर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित

कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

गतिरोध लंबे समय से चल रहा है, जिसके

रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा राजपार्क गुरुद्वारा

गुरुनानक देव की जयंती आज, जयपुर के सभी गुरुद्वारों को फूलों से सजाया



गुरुनानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर राजापार्क स्थित गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया गया।

जयपुर। सिख धर्म के प्रथम गुरु और शम तक भी धार्मिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। भाई ऑंकार सिंह, भाई तेजेंद्र सिंह और गुरमत प्रचारक विचारक ज्ञानी किशन सिंह साध संगत के समक्ष गुरुवाणी कीर्तन एवं गुरमत विचार प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान गुरु के उपदेश, जीवन दर्शन और इतिहास पर आधारित विचार साझा किए जाएंगे। इसके बाद प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए अरदास की जाएगी। इस पावन अवसर पर सरबत के भले की अरदास कर समूची मानवता के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी।

राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि जयपुर में आदर्श नगर राजापार्क, वैशाली नगर, कंवर नगर और

मानसरोवर गुरुद्वारों में बुधवार की सुबह से ही संगत पहुंचना शुरू हो जाएगी।उन्होंने बताया कि आदर्श नगर गुरुद्वारे में लगभग 25 हजार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहां श्रद्धालु मल्था टेकने के बाद दिनभर लंगर परसादी ग्रहण करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को भी विशेष फूलों और रोशनी से सजाया गया है। गुरुद्वारे के ज्ञानी जगदीश सिंह ने बताया कि गुरु ने कई उपदेश दिए हैं। इनमें गुरुनानक देव जी के उपदेश नाम जपों, किरत करो, वंड छको के भाव को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धालु सेवा और भक्ति में लीन रहेंगे। जयपुर में प्रकाश पर्व का यह आयोजन न केवल सिख समाज बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी श्रद्धा और एकता का प्रतीक बनेगा।

जयपुर डिस्कॉम ने श्री फेज के सभी खराब मीटर बदले

जयपुर । जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने सभी श्री फेज (गैर कृषि) उपभोक्ताओं के खराब विद्युत मीटर बदलने में कामयाबी हासिल की है। निगम के सभी 18 सर्किलों में सभी श्री फेज (गैर कृषि) विद्युत उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदलकर उनके स्थान पर नए कार्यशील मीटर लगा दिए गए हैं। डिस्कॉम को खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत शुल्क में छूट नहीं देनी होगी। इन उपभोक्ताओं को अब प्लेज बिल के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि श्री फेज (गैर कृषि), श्री फेज (कृषि), सिंगल फेज (शहरी) तथा सिंगल फेज (ग्रामीण) के 2 लाख 20 हजार से अधिक मीटर डिफेक्टिव होने के कारण निगम की वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि विद्युत शुल्क में छूट के रूप में उपभोक्ताओं को देनी पड़ी थी। जयपुर डिस्कॉम के प्रयासों का परिणाम है कि अब निगम के सभी सर्किलों में सिंगल फेज (शहरी एवं ग्रामीण), श्री फेज (कृषि एवं गैर कृषि) में खराब मीटरों की संख्या शटकर मात्र 19 हजार 303 रह गई है और यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम 6 माह में शटकर मात्र 12.50 लाख रूपए ही रह गई है।

डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले ड्राईवर के खिलाफ मामला दर्ज

—कार्यालय संवाददाता— जयपुर । विषयकमा स्थित लोहा मंडी में सोमवार की दोपहर नशे में धुत डंपर चालक ने एक कार चालक से मामूली कहासुनी के आवेश में आकर 14 लोगों को बेरहमी से कुचलता हुआ निकल गया था। हादसे के बाद मुख्य मार्गों में कोहराम मच गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच

दुर्घटना अनुसंधान इकाई की जगह हरमाड़ा थाना अधिकाारी उदयसिंह करेंगे। पुलिस इस प्रकरण की जांच भी आपराधिक मामले की तरह गहनता से करेंगी।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चायल दिप्रताप सिंह की शिकायत पर डंपर चालक कल्याण मल के खिलाफ धारा 105 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया की पूरा घटना क्रम उसकी आंखों के सामने हुआ। वो अपनी मां के साथ स्कूटी पर लोहामंडी की ओर जा रहा था। इसी

- **हरमाड़ा थाना इंचार्ज उदयसिंह करेंगे इस प्रकरण की जांच**
- **बीएनएस की धारा 105 में केस दर्ज, इसमें आजीवन या 10 साल तक की कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान है**

दौरान तेज रफ्तार डंपर लापरवाही तरीके से आया और पैदल जा रहे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। डंपर चालक ने कई दूधिया और चौपटिया लोगों को भी टक्कर मारी और दर्जनों लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ गया। एडवोकेट पंकज पंचलगनिया ने बताया कि पुरानी आईपीसी की धारा 3०4 के तहत आपराधिक मानव वध में लगाई जाती थी। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के तहत धारा 1०5 गैर -इरादतन हत्या की धारा जोड़ी जाती है। जिसमें आजीवन या 1० साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

तस्करी के दो आरोपियों को 2०-2० साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 2०-2० साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 7 नवम्बर 2०19 को काछोला थाना अधिकारी रतनलाल मय जांबा थाने से गश्त करते हुए लक्ष्मणगढ़ तिराहे पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक आया जिसे शंका के आधार पर चेक किया तो ट्रक में 40 कट्टे अफीम डोडा-चूरा भरा हुआ मिला जो अजवाइन, प्याज और लहसुन के कट्टों के नीचे दबा कर रखा हुआ था। ट्रक चालक से नाम-मुछा तो ट्रक चालक ने अपना नाम मदनलाल पुत्र बालू लाल प्रजापत निवासी रायपुर और खलासी ने अपना नाम सांवरलाल पिता महावीर प्रसाद रायपुर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा होना बताया। पुलिस ने अफीम डोडा-चूरा का तोल किया तो कुल वजन 1००0 किलो पाया गया। मुलजिम्ओं को



पुलिस ने आरोपियों को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया।

गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। ट्रायल पूरा होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस भीलवाड़ा जगदीश प्रसाद शर्मा ने मदनलाल और सवार को दोषी मानते हुए दोनों को 2०-2० साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोग अभियोजक गुर्जर ने आरोप सिद्ध करने के लिए 7 गवाह और 2०2 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए।

गेपसगार झील में कार व

बाइक गिरी : डूंगरपुर शहर में बादल

महल रिंग रोड पर सोमवार देर रात बाइक और कार के बीच टक्कर के बाद दोनों वाहन गेपसगार झील में गिर

गए। हादसे में बाइक सवार युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त और कार सवार युवक को लोगों ने बचा लिया।

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रोशन पुत्र भगवती शंकर हरसोत, निवासी पिंडावल के रूप में हुई है। वह डूंगरपुर

शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रोशन अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें हैं। सोमवार शाम वह लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गया था। इसके बाद अपने दोस्त अमन जैन के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान गेपसगार झील के बादल महल रिंग रोड पर सामने से आ रही एक कार से टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक और कार दोनों झील के पानी में जा गिरे। घटना के बाद रिंग रोड पर मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और अमन जैन व कार सवार युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन रोशन गहरे पानी में डूब गया। बाद में गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की खबर मिलते ही देर रात परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसे की प्राथमिक वजह अंधेरा और तेज रफ्तार वाहन हो सकती है। मामले की जांच की जा रही है।

हेल्प डेस्क में शिक्षकों को मुक्त करने की मांग

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला कलेक्टर बीकानेर एवं विभाजन अधिकारी को ज्ञापन भेज कर आग्रह किया है की विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के हेल्प डेस्क कार्यक्रम में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।

संगठन के प्रदेश बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने ज्ञापन में अवगत करया कि वर्तमान में सरकार द्वारा समय से पूर्व परीक्षा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है जिस कारण से विद्यालयों में पाठ्यक्रम भी पूर्ण नहीं हो पाया है। शिक्षकों पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने एवं फिर परीक्षाओं का संचालन नवंबर माह में ही करने का दबाव है। ऐसी स्थिति में एक ही समय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण एवं विद्यालयी कार्यों के पूर्ण करने के दोहरे राजकीय दायित्वों को लेकर असमंजसता की स्थिति बन गई है। आचार्य ने ज्ञापन में बताया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के अध्यक्ष का कार्य अन्य राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है लेकिन परीक्षाओं का संचालन एवं पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने का दायित्व केवल शिक्षक वर्ग ही पूर्ण कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखते हुए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा संचालन की कार्यों के दायित्व को पूर्ण करने में ही रहने देना चाहिए। ज्ञापन में अवगत करवाया कि जारी आदेशों में अहता दिनांक 1 जनवरी 26 के तहत

- राज. शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने बीकानेर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा**

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गठित होने वाली हेल्प डेस्क के लिए अधिकोश विद्यालयों में 2-2 बुथ होने के कारण एक विद्यालय से 6 शिक्षकों को लगाया गया है तथा जहां एक बुथ है वहां से 3 शिक्षकों को लगाया जाने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होगी और साथ ही विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। वर्तमान में 20 नवंबर से राज्य के सभी विद्यालयों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का संचालन होना है। वहीं परीक्षाएं निर्धारित समय से पूर्व प्रारम्भ होने के कारण विद्यालयों में पाठ्यक्रम बकाया चल रहा है जिसे पूर्ण करवाने का दबाव भी शिक्षकों पर है। ज्ञापन में पाठ्यक्रम पूर्ण करने, परीक्षा समय एवं उसी बीच पुनरीक्षण कार्यक्रम की हेल्प डेस्क में शिक्षकों को लगाये जाने से शिक्षण व्यवस्था एवं परीक्षाएं प्रभावित होने की स्थिति रहेगी, जिससे बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के सफल संचालन एवं अधूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने हेतु छत्र हित में उक्त हेल्प डेस्क कार्यक्रम से शिक्षकों को मुक्त करवाने का आग्रह जिला कलेक्टर से किया गया है।

मानसिक रूप से कमजोर महिला ने फांसी लगाई

श्रीडूंगरगढ़, (निसं)। यहां एक मानसिक रूप से कमजोर महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला ने शिवम मानव कल्याण सेवा संस्थान के कमरे में पछे से चुट्टी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 4० वर्षीय किरण पत्नी जितेंद्रसिंह निवासी सुडाबास, गोगामेडी, रतनगढ़ के रूप में हुई है। वह पिछले एक साल से

बिगाबास के वार्ड नंबर 24 में संचालित आश्रम में रह रही थी। सूचना मिलने पर डेड कॉन्टेन्टेल रामस्वरूप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। रामस्वरूप ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुरानी आबादी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर शहर से चोरी हुई 5 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। आरोपी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है।

एससुचन एं रजिस्टार ने बताया कि थाना इलाके से चोरी हो रही मोटरसाइकिलों की बरामदगी तथा आरोपी पकड़ने को एसपी डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर एसएसआई छिंद्रपालसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम ने 8 बाई मोहनपुरा व हाल 6 ए निवासी 24 वर्षीय

इस संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से भामाशाह दिलीपराज कोठारी ने प्रेरक पुष्पराज बोहरा तथा रविंद्र सिंह बालावत के साथ जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गावड़े से मुलाकात कर नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रदान किया। जिला कलेक्टर ने कोठारी के इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रसन्नता प्रकट की। जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास हेतु भामाशाह दिलीपराज कोठारी के महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया।

रावला मंडी में राशन वितरण बाधित

रावला मंडी, (निसं)। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण में बाधा आ रही है। सर्वर डाउन होने और ई-पोस मशीनों में स्टॉक अपडेट न होने के कारण उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं को राशन न मिल पाने का मुख्य कारण सर्वर की

खराबी और डीलरों की ई-पोस मशीनों में स्टॉक का अपडेट न होना है। गोदामों में राशन उपलब्ध होने के बावजूद, डीलरों के पास मशीन में जानकारी न होने से वितरण रुक गया है। इसके अलावा, कुछ ई-पोस मशीनें आधार ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण बंद पड़ी हैं।

जिला आपूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह समस्या सरकार द्वारा ई-पोस मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।



गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने संबोधित किया।

बन जाता है। कारण अलग-अलग होते हैं। बागडे ने कहा कि हमारे विघटन, हमारी गरीबी, हमारे एकसंघ नहीं होने का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने देश पर अतिक्रमण कर लिया। वह हमने अंग्रेजों से वापस लिया।

सम्मेलन में जाट समाज के 3० जोड़े परिणय सूत्र में बंधे



जाट समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हरणी महादेव भीलवाड़ा में सम्पन्न हुआ।

भीलवाड़ा, (निसं)। सकल जाट समाज द्वारा राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा, भीलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन हरणी महादेव भीलवाड़ा में सामाजिक एकता और सादगी का प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर 3० जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिन्होंने एक नए और समृद्ध जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में नव-दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथियों में राजस्थान जाट महासभा प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील, सारिका सिंह चौधरी (प्रदेशाध्यक्ष, महिला काँग्रेस, राजस्थान), और अंकलेश जाखड़

शामिल रहे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अदिति चौधरी, बदरी लाल जाट, महावीर चौधरी, एस.डी.एम. ओम प्रकाश माचरा, नगर निगम कमिश्नर हेमराम चौधरी, सीताराम चौधरी, हनुमान धायल (पुलिस निरीक्षक), देवीलाल चौधरी, राजवीर कुशवाह, होरा लाल भदाला, रामेश्वर जाट, प्रेमराम सियाग, गजराज चौधरी और जे.वी.पी. मीडिया ग्रुप चेयरमैन हरि राम किंवाड़ा मौजूद रहे। इस अवसर पर नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी ने सभी

उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। जाट समाज के प्रमुखों और सदस्यों ने इस मंच से सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि सामूहिक विवाह का यह आयोजन हर साल किया जाएगा, समाज के सभी लोग सामूहिक विवाह में ही अपने बच्चों की शादी करेंगे, शादियों में होने वाली होड़ा-होड़ी और फिजूलखर्ची (बर्बादी) से बचकर उस धन का उपयोग शिक्षा पर किया जाएगा। यह सामूहिक संकल्प समाज में एक नई दिशा देने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंच संचालन नारायण भदाला ने किया।

श्रीगंगानगर जिले में डेंगू रोगियों का आंकड़ा दो सौ के करीब

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में डेंगू रोगियों का आंकड़ा दोहरे शतक के करीब पहुंच रहा है। जिला अस्पताल में 4० सैपलों की एलाइजा जांच की गई। इनमें से पांच पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या 22 हो गई है। नए मरीज तीन जिला मुख्यालय से, एक सादुलशहर और एक पदमपुर ब्लॉक एरिया का रहने वाला है। वह विभाग का आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन इसमें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों का आंकड़ा शामिल नहीं है। यहां तक कि तपोवन में हो रही एलाइजा जांच के आंकड़े भी शामिल नहीं हैं। तपोवन में 27 एलाइजा टेस्ट किए गए। इनमें 12 पॉजिटिव आए हैं। इनमें से तीन

श्रीगंगानगर जिले के हैं, शेष फाजिल्का और अबोहर तहसील के हैं। एक अक्टूबर से अब तक के डेटा की बात करें तो 3 नवंबर को आधिकारिक आंकड़ा 78 जबकि कुल आंकड़ा 81 पहुंच गया है। एक जनवरी से अब तक यह आंकड़ा 189 पहुंच चुका है। जिला अस्पताल की डीसी डॉ. ज्योत्सना चौधरी ने बताया कि अस्पताल में डेंगू वार्ड में अभी मरीज भर्ती करने को पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। इसलिए वार्ड को नहीं बढ़ाया गया है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एसडीपी बनाने की प्रक्रिया सही चल रही है और जरूरत के हिसाब से मरीजों को एसडीपी दिया जा रहा है। स्थिति

नियंत्रण में है और मरीज उपचार के बाद ठीक होकर घर लौट रहे हैं। अभी वार्ड में 22 मरीज उपचारार्थीन हैं।

जिला अस्पताल में मच्छरों की फौज पर नियंत्रण के लिए प्रयास शुरू नहीं किए गए। नगरपरिषद से मनरेगा मजदूर आए ही नहीं। लिहाजा सफाई का अभियान छेड़ा ही नहीं गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पीएमओ की ओर से 3० मजदूर मांगे गए थे, लेकिन एक भी नहीं आया। दोपहर में पता किया तो नगरपरिषद की ओर से बताया गया कि गलतफहमी के कारण मजदूर नहीं भेजे जा सके। अस्पताल के स्टाफ ने भी बताया कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रयास नहीं हो रहे।

लोगों को नेशनल हाइवे निर्माण के नाम पर बेघर किया

भीलवाड़ा, (निसं)। नेशनल हाइवे 158 की परियोजना निदेशक ने झुठा वादा कर मकान तोड़ दिया। 7०० मीटर के अधूरे हाइवे निर्माण की दुर्दशा ऐसी कि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 मांडल आसीद रास को बनकर तैयार हुए 3 साल हो गए हैं, इस नेशनल हाइवे



राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के नाम पर लोगों के घर तोड़ दिये।

रहने को मजबूर हो गए हैं। तीन साल में अधूरे हाइवे निर्माण और इस क्षतिग्रस्त हाइवे पर कई अधिकारी व राजनेताओं का गुजरना हुआ, निर्माण कार्य पूरा करने की बात पर परियोजना निदेशक राकेश कुमार से इन अधिकारियों राजनेताओं ने संपर्क किया तो हमेशा टालमटोल का जवाब मिला। सरकार की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के आसीद सवाईभोज दौर

के दौरान भी परियोजना निदेशक को जमकर फटकार लगाई गई। कस्बे वासियों ने परियोजना निदेशक राकेश कुमार पर आरोप लगाए कि उनसे झुठा वादा कर उनके मकान तोड़ दिए गए। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने बताया कि परियोजना निदेशक की फोन लगाए गए लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं।

शिक्षक पिता के पुत्र ने विद्यालय का काहिया पलट का फैसला लिया

जालोर, (कासं)। जालोर शहर के मूल निवासी एवं वर्तमान में प्रवासी व्यवसायी दिलीपराज कोठारी ने अपने पिताजी अमृतराज कोठारी की स्मृति को चिर स्थाई बनाने के लिए कुछ हटकर बड़ा फैसला किया है। स्थानीय समाज सेवक एवं व्यवसायी पुष्पराज बोहरा की प्रेरणा से दिलीपराज कोठारी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, शिवाजी नगर जालोर की कायापलट करने के लिए संकल्पित हुए, जिसमें कभी उनके पिताजी अमृतराज कोठारी ने शिक्षक एवं संस्था प्रधान के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। दिलीपराज कोठारी की शिक्षा-

दीक्षा जालोर में हुई तथा शिक्षा उपरांत व्यवसाय के उद्देश्य से बैलूचू प्रवास किया। वर्तमान में एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित दिलीपराज अपनी जड़ों को नहीं भूले तथा प्रेरक पुष्पराज बोहरा एवं अपने मित्र एवं राजनेता रविन्द्र सिंह बालावत से चर्चा कर कोठारी-भण्डारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जालोर-बैलूचू के माध्यम से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, शिवाजी नगर, जालोर के नवीन भवन निर्माण का फैसला किया, ताकि समाप्तित शिक्षक रहे पिताजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाया जा सके।

इस संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से भामाशाह दिलीपराज कोठारी ने प्रेरक पुष्पराज बोहरा तथा रविंद्र सिंह बालावत के साथ जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गावड़े से मुलाकात कर नवीन भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रदान किया। जिला कलेक्टर ने कोठारी के इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रसन्नता प्रकट की। जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास हेतु भामाशाह दिलीपराज कोठारी के महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया।

बांसवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल एवं

कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में “राष्ट्रीय एकात्मता : विविधता में एक चेतना” विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने संगोष्ठी के अंतर्गत जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करते हुए कहा कि राष्ट्र अनेक भाषा, संस्कृति, मतों, परंपराओं से मिलकर बनता है राष्ट्र की एक सीमा होती है। राष्ट्र में उस देश का नागरिक रहता है। कोई दूसरे देश का नागरिक आता है तो उसे उस देश की नागरिकता लेनी पड़ती है। संगठित जनसमुदाय, निश्चित भूभाग, संस्कृति, परंपरा, एकता की भावना हमें एक सूत्र में बांधती है। देश के नागरिकों में देश के मूल्यों, आदर्शों, मातृभूमि, समुदाय के प्रति निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एकता की भावना सिर्फ बातों में नहीं व्यक्ति के कर्मों में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश जब बनता है तब एक देश से दूसरा देश

एक राष्ट्र विकसित बनता है जब नागरिक एकजुट होकर देशप्रेम के साथ अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। नागरिक अपनी शक्ति, बुद्धि, त्याग, आर्थिक स्वावलंबन से देश को विकसित बनाते हैं। उन्होंने कहा

कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। पहले गांव व कच्चे मकान होते थे जो अब पक्के बन गए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है। देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ

